

भारत सरकार  
पोत परिवहन मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4798 जिसका उत्तर और  
गुरुवार, 30 मार्च, 2017/9 चैत्र, 1939 (शक) को दिया जाना है  
जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन के माध्यम से यातायात

4798. डॉ. उदित राज :

श्री कोनाकल्ला नि नारायण राव

श्री मुल्लापल्लीन रामचन्द्रम

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) परियोजना -वार सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय संदर्शी योजना की कार्यान्वयन स्थिति क्या है
- (ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु विभिन्न समितियां गठित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इनका क्या योगदान है
- (ग) क्या सरकार को केरल सरकार से सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है
- (घ) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित तटीय आर्थिक जोन (सीईजेड) की वर्तमान स्थिति क्या है
- (ङ.) क्या सरकार का विचार सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत नए पोत नों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (च) क्या आंध्र प्रदेश में रम्मधयापहनम में नया पोत न स्थापित किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (छ) सागरमाला के अंतर्गत परियोजना हेतु कुल कितना व्यय किया गया है और निधियां किस ढंग से जुटाई जाने की संभावना है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्यस मंत्री  
(श्री पोन्. राधाकृष्णसन)

(क) भारत की तटरेखा तथा समुद्री क्षेत्र के व्यापिक विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। सागरमाला के एक हिस्से के रूप में लगभग 8 लाख करोड़ रु के एक अनुमानित निवेश पर (अनुबंध) पत्तसन आधुनिकीकरण एवं नए पत्तान का विकास, पत्तनन संपर्कता को बढ़ाया जानापत्तधन से जुड़े औद्योगिकीकरण तथा तटीय समुदाय विकास के क्षेत्रों में 400 से अधिक परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। सागरमाला के अंतर्गत चुनी गई परियोजनाओं को संगत केन्द्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों महापत्तनों तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रमुखतः निजी क्षेत्र की भागीदारी अथवा पी पी पी माध्यम से कार्यान्वित किया जाने पर विचार किया जाएगा। अतः उपर्युक्त परियोजनाओं का ब्यौराकार्यान्वयन समय सीमाओं तथा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने हेतु संगत केन्द्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों से साझा किया गया है। कुल 214 परियोजनाएँ पहले से ही कार्यान्वयन तथा विकास के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं (अनुबंध-2)।

(ख) सागरमाला संस्थापगत संरचना के एक भाग के रूप में 13 मई 2015 को राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (एन एस ए सी) का गठन किया गया तथा अब तक दो बैठकें की जा चुकी हैं। एन एस ए सी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना कार्यान्वयन सहित एन पी पी के नियोजन एवं कार्यान्वयन के विभिन्न पक्षों की समीक्षा करता है। सागरमाला समन्वयन एवं स्टीनयरिंग समिति का गठन 8 जुलाई 2015 को किया गया था और अब तक 3 बैठकें की गई हैं। एस सी एस सी कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है तथा परियोजना वित्त पोषण/ समन्वयन से संबंधित विषयों पर विचार करती है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी तथा अंडमान-निकोबार, की सरकारों ने राज्य सागरमाला समितियों का गठन किया है। एस एस समितियों की बैठकें गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार में आयोजित की गई हैं। एस एस समितियों राज्य स्तर सागरमाला से संबंधित परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करने को सुकर बना रही हैं।

(ग) पोत परिवहन मंत्रालय को केरल सरकार से तीन प्रस्ताव अर्थात् विजिंझम पत्तन तक रेल संपर्क, अजिंकल पत्तन का विकास तथा कोल्लम पर बहुउद्देशीय घाट, सागरमाला के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त हुए हैं। विजिंझम रेल संपर्कता के लिए राज्य सरकार को भूमि का अधिग्रहण करने तथा परियोजना के वित्त पोषण के लिए व्यवहार्यता अंतर

वित्तिपोषण मार्ग ढूँढने की सलाह दी गई है। केरल सरकार से अजिझकल पत्न्िए के फ्रेज-के विकास हेतु व्य वहार्यता स्थासपित करने के लिए कुछ तकनीकी अध्ययन करवाए जाने की सलाह दी गई है। पोत परिवहन मंत्रालय ने केरल सरकार से एक विस्तृछत प्रस्ता व प्रस्तु त करने का अनुरोध किया है। कौल्ल म में एक बहुउद्देश्यत घाट के विकास के लिए केरल सरकार से विस्तृ त परियोजना रिपोर्ट पर स्पएष्ठी करण मांगे गए हैं।

(घ) सागरमाला कार्यक्रम (2016-2035) को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत विकास हेतु चौदह (14) तटीय आर्थिक जोन (सीई जेड) चुने गए हैं। सी ई जेड्स की परिप्रेक्ष्य योजना को संगत राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। प्राप्त हुए भूमि ब्यौतरे के आधार पर आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में सी ई जेड्स के लिए विस्तृत मास्टबर् प्लान तैयार करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों से भूमि ब्यौतरे देने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) तथा (च) सागरमाला कार्यक्रम के भाग के रूप में छः (6) नए पत्तिन स्थलों की पहचान की गई है अर्थात वधावन, एनायम, सागरद्वीप, पारादीप बाहरी बंदरगाह, सिरकाड़ी तथा बेलेकेरी, इन 6 पत्तिन स्थलों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई है। सागरद्वीप पर नए पत्तिन के लिए डी पी आर तैयार कर ली गई है तथा वधावन, पारादीप, बाहरी बंदरगाह तथा एनायम के लिए तैयार की जा रही हैं। एनायम में एक महापत्तिन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 5 जुलाई 2016 को हासिल कर लिया गया है। जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचना दी गई है, रामायापट्टणम को राज्य सरकार द्वारा गैर महापत्तिन के रूप में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है तथा यह कृष्णायपट्टणम के विस्तारित अनन्ये अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अवस्थित है।

(छ) सागरमाला कार्यक्रम (2016 - 2035) के एक हिस्से के रूप में, 400 से अधिक परियोजनाओं की अनुमानित 8 लाख करोड़ ₹ के निवेश की पहचान की गई है। सागरमाला के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन को केन्द्रिय लाइन मंत्रालय, राज्य सरकारों/ समुद्री मंडल द्वारा पूरा किया गया है और एए पी वी निजी सेक्टर के माध्यम से और सार्वजनिक निजी सेक्टर के माध्यम से और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) के माध्यम से जो भी व्यावहार्य अधिमाम्य है।

शेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए , कोष संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों , राज्य सरकारों के बजट में से प्रार्थित होगा जो परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा। मंत्रालय / राज्य सरकारें / समुद्री मंडल ऐसे पहचान किए गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगी चाहे अपने बजट से अथवा एस पी वी के माध्यम से जहाँ पर सागरमाला विकास कम्पनी लिमिटेड (एस डी सी एल) इक्विटी समर्थन प्रदान करेगा , जैसा अपेक्षित और आवश्यक होगा।

महापत्तेनों में क्षमता वृद्धि ओर पत्तदन आधुनिकीकरण के संबंध में परियोजनाएं पी पी पी मोड के माध्यम से प्राथमिक तौर पर कार्यान्वित की गई हैं। इसके साथ-साथ महापत्तानों के आंतरिक अतिरिक्तर बजटीय संसाधनों को वित्त पोषण पत्तकन संबंधी परियोजनाओं के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। तटीय समुदाय विकास से संबंधित परियोजनाएँ पशुपालन , डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डी ए डी एफ) कोशल विकास और उधमी मंत्रालय (एम एस डी ई) की परियोजनाओं की एकजुट होकर कार्यान्वित किया जा रहा है

**अनुबंध-1**

**सागरमाला के अन्तर्गत परियोजनाओं का सार**

परियोजना विकास	वित्तीय वर्ष 15-16		वित्तीय वर्ष 16-17		वित्तीय वर्ष 17-18		वित्तीय वर्ष 18-19		वित्तीय वर्ष 19-20 से वित्तीय वर्ष 24-25 तक		वित्तीय वर्ष 25-26 से वित्तीय वर्ष 34-35 तक		कुल	
	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रु में)
पत्तकन आधुनिकीकरण	6 2	27,700	46	22,670	13	2,193	20	35,512	27	26,588	21	28,165	189	142,828
सम्पर्कता आवर्धन	3 0	15,881	58	28,924	28	16,64 1	26	139,71 5	17	21,182	11	8,233	170	230,576
पत्तकन आधारित औद्योगिकिकरण	2	325	1	3,000	2	5,000	17	94,426	11	318,13 0	-	-	33	420,881
तटीय समूदाय विकास	4	79	4	529	3	119	4	688	8	2,800	-	-	23	4,216
<b>कुल</b>	<b>9 8</b>	<b>43,985</b>	<b>109</b>	<b>55,123</b>	<b>46</b>	<b>23,95 3</b>	<b>67</b>	<b>270,34 1</b>	<b>63</b>	<b>368,70 0</b>	<b>32</b>	<b>36,398</b>	<b>415</b>	<b>798,500</b>

कार्यान्वयन एवं विकास के विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत परियोजनाओं का सार

कार्यान्वयनधीन परियोजनाओं का सार			
क्रम सं.	घटक	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु में)
1	पत्त न आधुनिकीकरण	69	31,150
2	पत्त न सम्पर्कता आर्वधन	57	39,309
3	पत्त न आधारित औधोगिकरण	3	26,325
4	तटीय समुदाय विकास	3	90
कुल		132	96,874

विकास के अधीन परियोजनाओं का सार			
क्रम सं.	घटक	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु में)
1	पत्त न आधुनिकीकरण	40	21,828
2	पत्त न सम्पर्कता आर्वधन	39	16,031
3	तटीय समुदाय विकास	3	516
कुल		82	38,374

\*\*\*\*\*